

भारत-सिंगापुर के बीच अमल में आया डीटीए

समाचारों में क्यों?

भारत सिंगापुर के बीच दोहरे कराधान समझौता (double tax avoidance agreement-DTAA) अमल में आ गया है, जिससे दोनों ही देशों को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होने की पूरी सम्भावना है। डीटीए संशोधन के इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये जाने से भारत और सिंगापुर के बीच कर स्थिरता सुनिश्चित होगी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, इससे दोनों देशों के बीच पारदर्शिता के साथ ही नविश, प्रौद्योगिकी एवं सेवाओं का प्रवाह बढ़ेगा।

भारत-सिंगापुर डीटीए के लाभ

- वदिति हो क आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिये भारत और सिंगापुर ने एक तीसरे प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके दोहरे कराधान से बचाव संबंधी समझौते (डीटीए) में संशोधन करने का फैसला किया था। संशोधन के अंतर्गत भारत ने राजस्व की हानि और काले धन को वापस लाने संबंधी समस्याओं के हल के रूप में जानकारी के आदान-प्रदान को स्वतः-आधारित बनाने पर ज़ोर दिया था।
- गौरतलब है कि भारत और मॉरीशस के बीच डीटीए में संशोधन से संबंधित एक ऐसा ही समझौता पहले ही अमल में आ चुका है, जिसमें भारत को मॉरीशस के रास्ते होने वाले नविश पर पूंजीगत लाभ कर लगाने का अधिकार मिला गया था।
- गौरतलब है कि मानक लेखा प्रक्रियाओं द्वारा कर पारदर्शिता को सुधारने के उद्देश्य से आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के सदस्य देशों के साथ दो दशक लंबी वार्ताओं के बाद डीटीए समझौता संपन्न हो पाया है। भारत सहित दुनिया भर के 101 देश डीटीए समझौते को लेकर प्रतिबद्ध हैं।
- ओईसीडी नियमावली के अनुसार, इन सभी 101 देशों के बैंक दूसरे देशों के लोगों की पहचान करके उनसे जुड़ी जानकारी संबंधित देशों के कर विभागों को उपलब्ध कराएंगे। वदिति हो किये सूचनाएँ अन्य देशों के साथ हर साल साझा की जाएंगी। इसके तहत लोगों के बैंक खातों, खातों से संबंधित ब्योरे, खाते में अर्जति आय और खाताधारक की पहचान से संबंधित जानकारी स्वतः साझा की जाएंगी।

नषिकर्ष

- ध्यातव्य है कि पनामा, बहामास, मॉरीशस, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों को आमतौर पर 'टैक्स हैवन' माना जाता है, यहाँ लोग कर चोरी से बचाए गए अपने काले धन को जमा करते हैं। भारत जहाँ मॉरीशस से पहले ही ऐसे समझौते को अमल में ला चुका है वहीं अब यह घटनाक्रम काले धन पर अंकुश लगाने के क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
- सिंगापुर से भारत के पूंजी बाज़ार में वदेशी नविश का बड़ा हस्सा आता है। गौरतलब है कि वर्ष 2015 के मार्च-अप्रैल की अवधि में भारत में वदेशी नविश के मामले में सिंगापुर पहले स्थान पर था। भारत और सिंगापुर द्वारा अमल में लाए जा रहे डीटीए का यह तीसरा प्रोटोकॉल संशोधन, शेयरों के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजी को स्रोत आधारित कराधान प्रदान करने के लिये 1 अप्रैल, 2017 से लागू हो जाएगा।
- वर्तमान में भारत-सिंगापुर डीटीए, एक कंपनी में शेयरों पर पूंजीगत लाभ के लिये नविश आधारित कराधान प्रदान करता है। वर्ष 2019 से सिंगापुर, सिंगापुर में भारतीयों द्वारा किये गए नविश की जानकारी भारत को देगा और इससे कर चोरी के एक प्रचलित माध्यम को बंद किया जा सकता है।